बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 55 ● नई दिल्ली ● शनिवार 06 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली पुलिस का समयपुर बादली में अवैध बार क्लब पर छापा, संचालक समेत 25 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली क्षेत्र में देर रात अवैध रूप से चल रहे बार-कम-क्लब का भंडाफोड़ कर 25 लोगों को पकड़ लिया है, जिनमें संचालक, ग्राहक और स्टाफ शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, 3 और 4 दिसंबर की रात यह कार्रवाई तब की गई जब सूचना मिली कि समयपुर मेन चौक स्थित एक इमारत की दूसरी मंजिल पर अवैध बार संचालित हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कई पुरुषों को संदिग्ध तरीके से इमारत में प्रवेश करते देखा। डीसीपी (आउटर नॉर्थ) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि टीम ने ठनका पीछा किया और श्री बॉक्सेज कैफे नाम से चल रहे एक कैफे में पहुंची, जहां तेज आवाज में संगीत बज रहा था.

दिल्ली में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस का हमला, सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग

नई दिल्ली । दिल्ली में लगातार बढ़ते कैंसर के मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. आईसीएमआर-नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के नए आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकारों पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि, राजधानी की स्थिति भयावह होती जा रही है और सरकारें आंखें मूंदकर बैठी हैं. यादव ने कहा कि राजधानी में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हालिया आंकड़े बेहद चिंतजनक हैं. 2024 में 28,387, 2023 में 27,561 और 2022 में 26,735 मामले दर्ज किए गए. उनके अनुसार, कैंसर सुनते ही मरीज अपनी जिंदगी का अंत समझने लगता है, लेकिन सरकारें आधुनिक इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रही हैं. उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार और मौजूदा बीजेपी शासित रेखा गुप्ता सरकार दोनों पर स्वास्थ्य ढांचे की बदहाली को लेकर निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने बताया कि पूरे देश में 2024 में 15.33 लाख से अधिक कैंसर मामलों का दर्ज होना इस खामोश महामारी का पैमाना बताता है. उन्होंने कहा, दिल्ली में

जनसंख्या घनत्व के मुकाबले कैंसर की दर देश में सबसे अधिक है. कैंसर विशेषज्ञों के हवाले से उन्होंने कहा कि, दिल्ली की जहरीली हवा, तनाव, धूलकण और बढ़ता प्रदूषण भी इस बीमारी के बड़े कारक हैं. देर से पहचान होने के कारण भी मामलों की संख्या हर साल बढ़ रही है. देवेंद्र यादव ने फेफड़ों के कैंसर पर बढ़ते जोखिम का जिक्र करते हुए कहा कि जब हवा ही जहरीली हो, तो बीमारी का फैलाव रुकना मुश्किल है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की कि दिल्ली भर में बड़े स्तर पर कैंसर जागरूकता अभियान चलाया जाए और सरकारी अस्पतालों में स्क्रीनिंग एवं आधुनिक इलाज सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जिससे गरीब मरीजों को राहत मिल सके. यादव ने कहा कि मिलावटी खाने-पीने की चीजें, तंबाकू और शराब का उपयोग कैंसर फैलाने वाले प्रमुख कारणों में हैं.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार खुद इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति देकर करोड़ों का राजस्व कमाती है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह मरीजों के लिए दवाइयों और स्क्रीनिंग की मुफ्त सुविधा भी सुनिश्चित करे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों की बदहाली के कारण गरीब मरीज इलाज न करा पाने की स्थिति में हैं. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के चलते कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की नकली दवाएं खुलेआम बिक रही हैं, जिससे मरीज इलाज के बजाय जान गंवा रहे हैं. उन्होंने इसे दिल्ली के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताया.यादव ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 0-74 वर्ष आयु वर्ग में हर 6 पुरुषों में एक और हर 7 महिलाओं में एक को जीवनकाल में कैंसर होने की आशंका है. पुरुषों में कैंसर निदान की औसत आयु 58 वर्ष और महिलाओं में 55 वर्ष बताई गई है, जो राजधानी के वातावरण और प्रदूषण स्तर की भयावह तस्वीर पेश करती है. दल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर 400+ के ऊपर बना रहने के लिए भी यादव ने सीधे तौर पर रेखा गुप्ता सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि प्रदूषण, खराब स्वास्थ्य-ढांचा और सरकारी उदासीनता मिलकर राजधानी को बीमारी की दलदल में धकेल रहे हैं.

अमित शाह ने स्वदेशोत्सव 2025 का किया उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिला नया मंच

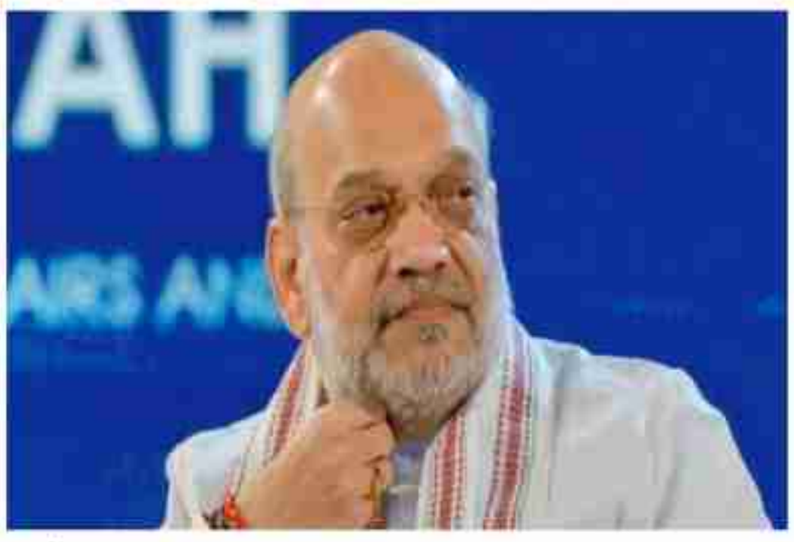

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय मैदान में स्वदेशोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित थे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह राष्ट्रव्यापी एक्सपो 5 दिसंबर, 2025 से 9 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद, गृह मंत्री ने स्वदेशी की शक्ति का प्रतीक स्वानुभूति प्रदर्शनी का भी अनावरण किया। इस स्वदेशी उत्सव के दौरान ज्ञान और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सेमिनार आयोजित किए गए हैं, ऐसा विज्ञप्ति में कहा गया है। तदनुसार, 5 दिसंबर को उद्घाटन दिवस पर पर्यावरण संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 6 दिसंबर को स्टार्टअप उड़ान 2025 और स्वदेशी संकल्प अभियान पर सत्र निर्धारित हैं। 7 दिसंबर के सत्र मातृशक्ति की भूमिका और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर केंद्रित होंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 8 दिसंबर को आयुर्वेद और स्वास्थ्य के साथ-साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सेमिनार होंगे। अंतिम दिन, 9 दिसंबर को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर चर्चा होगी। साथ ही, प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से रात 10:00 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।स्वदेशोत्सव ज्ञान, कला और स्वदेशी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करेगा। विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर स्वर्णिम जागरण मंच के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

आतंकी उमर की मदद करने वाले शोएब को राहत नहीं, एनआईए कस्टडी 10 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली ।

लाल किला बम ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी फरीदाबाद निवासी शोएब की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत 10 दिनों के लिए और बढ़ा दी है।

यह निर्णय तब आया जब शोएब की पूर्व में दी गई 10 दिनों की कस्टडी समाप्त हो गई और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। लाल किला बम ब्लास्ट मामला एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। उसकी पिछली हिरासत के दौरान एनआईए ने उससे गहन पूछताछ की थी और मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाने का प्रयास किया था। 10 दिनों की कस्टडी समाप्त होने के बाद, शोएब को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एनआईए ने कोर्ट से आरोपी की कस्टडी बढ़ाने की मांग की, जिसके पीछे मामले की आगे की जांच, अन्य आरोपियों की पहचान और संभावित षड्यंत्र के खुलासे जैसे तर्क दिए गए। कोर्ट ने एनआईए की दलीलों को स्वीकार करते हुए शोएब को 10 दिनों की और एनआईए कस्टडी में भेज दिया है।

मंदिर में दीया जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, उच्च न्यायालय के आदेश को दी चुनौती

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी, जिसमें मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीये को प्रवलित करने के उच न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की दलीलों को सुना और कहा कि याचिका को एक पीठ के सामने सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। मद्रास उच न्यायालय ने अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर

के श्रद्धालुओं को थिरुप्रनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पारंपरिक कार्तिगई दीपम को प्रवलित करने की मंजूरी दी थी। पत्थर के जिस दीए दीपाथून को प्रवलित किया जाना है, वह एक दरगाह के नजदीक है। इसे ही लेकर विवाद है। मद्रास उच न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को मदुरै जिलाधिकारी और शहर के पुलिस कमिश्नर की एक इंट्रा-कोर्ट अपील खारिज कर दी थी और श्रद्धालुओं को दीप प्रजवलित करने की मंजूरी दी थी। जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल 1 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दीपाथून पर दीया प्रवलित करने की जिम्मेदारी अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि ऐसा करना नजदीकी दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है। हालांकि एकल पीठ के आदेश के बावजूद दीप प्रवलित नहीं किया गया, जिसके बाद 3 दिसंबर को पीठ ने श्रद्धालुओं को दीप प्रवलित करने को कहा और सीआईएसएफ को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ मुदरै के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की। हालांकि उच न्यायालय ने इस अपील को खारिज कर दिया।

दिल्ली में प्रदूषण से परिंदे भी बेबस, आसमान में उखड़ रही सांस; स्मॉग में दबी चहचहाहट

नई दिल्ली ।

दिल्ली-एनसीआर इन दिनों जहरीली हवा की गिरफ्त में है और इसका दुष्प्रभाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा है। हवा में बढ़ते धूलकण, जहरीली गैसें और घने स्मॉग ने पूरे पर्यावरण को बीमार-सा बना दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहां इंसानी जीवन मुश्किल होता जा रहा है, वहीं बेजुबान पशु-पक्षी भी प्रदूषण की मार को चुपचाप सह रहे हैं। कुदरत नहीं इंसानों की वजह से निरंतर बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने पक्षियों के श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसकी वजह से वह ऊंची उड़ान भी नहीं भर पा रहे हैं। बेजुबानों के लिए हालत इस कदर खराब हो गए हैं कि कई पक्षियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। यही वजह है कि सुबह सुनाई देने वाली पक्षियों की चहचहाहट भी कम सुनाई दे रही है। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो दिल्लीडुएनसीआर की जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य दोनों ही गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेताया है कि वायु प्रदूषण सिर्फ पक्षियों को ही नहीं बल्कि कीड़े-मकौड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो स्वयं पक्षियों का भोजन होते हैं। इस तरह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। अरावली और नीला हौज जैव विविधता पार्क के साइंटिस्ट इंचार्ज डॉ. शाह हुसैन कहते हैं कि पक्षियों के फेफड़े इंसानों से यादा नाजुक होते हैं, इसलिए प्रदूषण का असर उन पर अधिक गंभीर होता है। दिल्ली के चिकित्सालयों और रेस्क्यू सेंटर्स में घायल पक्षियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें कबूतर, तोते, चील, कोयल, कौए आदि शामिल हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले कबूतरों के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रदूषण पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया, तो आने वाले समय में पक्षियों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। कभी जहां नीली खुली हवा में हम पंख फैलाकर उड़ा करते थे,वहीं अब हर सांस भारी हो गई है।हमारे छोटे-छोटे फेफड़े इस धुएं में घुटते हैं। पेड़ जिन पर हम बैठते थे, वही बीमार पड़ गए हैं। कभी सूरज की दिशा देखकर उड़ने वाले हम,अब धुएं की मोटी चादर में रास्ता टटोलते रहते हैं। हम चहकते थे, अब हम खामोश हैं। हम हवा के सहारे उड़ते थे, अब वही हवा हमें गिरा देने पर तुली लगती है।

पक्षियों की सेहत पर दिख रहा असर

वजीराबाद स्थित वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष मोहम्मद सऊद ने बताया कि प्रदूषण का सीधा असर पक्षियों की सेहत पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आसमान ही पक्षियों का घर होता है, लेकिन इंसानों की लापरवाही के कारण अब ये घर भी प्रदूषण से भर गया है। हाल ही, में एक घायल कोयल को उनके पास लाया गया, जिसे सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। अरावली जैव विविधता पार्क की वन्यजीव पारिस्थितिकीविद डॉ. आयशा सुल्ताना ने कहा कि शहरी इलाकों के साथ-साथ जंगलों में रहने वाले पक्षी भी प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने से उनका भोजन ढूंढना कठिन हो गया है। वह बताती हैं कि जब पक्षियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो उनकी प्रजनन क्षमता घटने लगती है।

अस्पताल में हर दिन 10 से 12 घायल या बीमार पक्षी पहुंच रहे

भोजन न मिलने से उनके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। यह स्थिति उनकी प्रजनन क्षमता तक प्रभावित कर रही है। पुरानी दिल्ली स्थित दिगंबर जैन लाल मंदिर के पक्षियों के धर्मार्थ चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. हरअवतार सिंह बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पक्षियों में श्वसन संक्रमण और कमजोरी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब पक्षी पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो उड़ान भरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अस्पताल में हर दिन 10 से 12 घायल या बीमार पक्षियों को लाया जा रहा है। मौजूदा समय में यहां 200 से 250 पक्षियों का इलाज चल रहा है।

पंजाब को मरहम चाहिए, छेड़खानी नहीं

यह सरकार कदम वापिस लेने के लिए जानी नहीं जाती। पर अगर कृषि से सम्बन्धित तीन कानून वापिस लेना भी शामिल किया जाए तो पंजाब सम्बन्धित तीन बड़े कदम इस सरकार ने वापिस लिए हैं। यह अच्छी बात भी है। लोकतंत्र में अलोकप्रिय कदम वापिस लेना समझदारी और संवेदनशीलता दिखाता है। पर सवाल तो है कि इस समय जबकि पंजाब भीषण बाढ़ से गुजरा है, आर्थिक हालत नाज़ुक है और प्रदेश गुरु तेगबहादुर के 350वें शहीदी दिवस से सम्बन्धित समागमों में व्यस्त है, एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए ही क्यों गए? पंजाब एक बार्डर स्टेट है जिसके लोगों का संघर्ष का लम्बा इतिहास है। यहां लोगों से संवाद किए बिना छेड़खानी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कृषि सम्बन्धी कानून लाते समय भी गजब का प्रशासनिक अहंकार और लापरवाही दिखाई गई थी। अब फिर वही गलती की गई है। पंजाब को ठीक तरह से समझने में बार-बार इतनी नासमझी क्यों दिखाई जा रही है? पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के संचालन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। लाहौर में इसकी स्थापना 1882 में हुई थी जहां अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी है। स्वतंत्र भारत में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना चंडीगढ़ में हुई जहां इसका खूबसूरत कैम्पस है। यह पंजाब की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। पंजाब को शिक्षित करने में इसका बड़ा योगदान है। पंजाबियों का उससे भावनात्मक जुड़ाव भी है। मैं भी यहां से पढ़ा हूं और मेरे माता-पिता भी लाहौर में इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। अक्तूबर में इस यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर चोट करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसके सेनेट के चुनावों में भारी परिवर्तन कर दिया था। सेनेट के सदस्यों की संख्या 91 से घटा कर 31 कर दी गई थी। प्रभाव यह गया कि केन्द्र की सरकार विश्वविद्यालय की आज़ादी खत्म कर अपना कंट्रोल करना चाहती है। इस पर भारी प्रतिक्रिया हुई। बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। दो यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ी। 27 दिनों के प्रदर्शन ने पंजाब के राजनीतिक और सामाजिक वर्ग (भाजपा को छोड़ कर) को एक मंच पर केन्द्र के विरुद्ध इकट्ठा कर दिया और केन्द्र को कदम वापिस लेने पर मजबूर कर दिया। नेपाल में जेन-जेड के प्रदर्शन के बाद वैसे भी आजकल सरकारें छात्र असंतोष से घबराती हैं। नए चुनाव की घोषणा कर दी गई है और अब यह 91 सीटों के लिए ही होंगे। आशा है कि स्टूडेंट्स पर जो एफआईआर और केस दर्ज किए गए हैं वह भी वापिस ले लिए जाएंगे। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता मिली हुई जिस कारण वह सही शिक्षा दे रहे हैं। सोचने और अभिव्यक्ति की आजादी को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे देश में चाहे वह जेएनयू हो या पंजाब यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, यह सब अपनी शैक्षणिक आज़ादी के लिए जानी जाती हैं। हार्वर्ड या कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसलिए इतने मशहूर है क्योंकि वहां सोचने और बोलने की आज़ादी है। हर हुक्मरान को ऐसी आज़ादी चुभती है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी हार्वर्ड पर धावा बोल दिया था। उसकी केन्द्रीय फंडिंग रोक दी थी। ऐसे लोग समझते नहीं कि अगर सोचने के अधिकार पर पहरा बैठा दिया गया तो देश की तरक्की बाधित हो जाएगी। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि केन्द्र ने एक और बड़ा कदम उठाने की मंशा प्रकट कर दी जिससे पंजाब में तूफान खड़ा हो गया। मामला चंडीगढ़ से सम्बन्धित था। लोगों के दबाव में यह कदम भी वापिस ले लिया गया, पर यह उठाया ही क्यों गया, यह जानते हुए कि चंडीगढ़ के साथ पंजाबियों का भावनात्मक रिश्ता है? यह शहर संवैधानिक हैसियत में कोई भी परिवर्तन जो पंजाब से इसका रिश्ता कमजोर करता हो, को पसंद नहीं करेंगे। जिसे 'सिटी ब्यूटीफुल' कहा जाता है, यह नया शहर जवाहरलाल नेहरू की उन लोगों के लिए सौगात थी जिन्हें देश का विभाजन जख्मी छोड़ गया था। नेहरू जी ने उनके दर्द को समझा था। उनकी राजधानी लाहौर पाकिस्तान में रह गई थी। चंडीगढ़ लाहौर तो नहीं है क्योंकि वह इतिहास नहीं हो सकता, पर यह एक ऐसा शहर है जिस पर हम नाज़ कर सकते हैं। केन्द्रीय शासित होने के कारण चंडीगढ़ पर पैसा भी खूब बहाया जाता है। पंजाब के बाकी जर्जर शहरों और चंडीगढ़ के बीच तो ज़मीन-आसमान का अंतर है। चंडीगढ़ लाहौर की एवज में पंजाब को दिया गया था। प्रसिद्ध स्विस-फ्रैंच आर्किटैक्ट ली कार्बूजिए को बुला कर नेहरू जी ने खुद दिलचस्पी लेकर इसका निर्माण करवाया था। कई शायर इसकी वास्तुकला की आलोचना कर चुके हैं। एक सज्जन जो हमें पढ़ाते थे, ने कविता लिख कर शिकायत की थी कि यह 'पत्थरों का शहर है, पत्थर दिलों का शहर है'। तब से लेकर चंडीगढ़ बहुत बदल गया है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके अस्तित्व को लेकर विवाद जुड़ गया है जिसका समाधान नज़र नहीं आ रहा। केन्द्र के वर्तमान कदम ने इस सोए हुए मामले को फिर से भड़का दिया है। जब इसे पंजाब के लिए बनवाया गया था तो यह वह पंजाब था जो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। मनाली और रोहतांग दर्रा तक पंजाब का हिस्सा था। जब 1966 में पंजाब का भाषा के नाम पर विभाजन किया गया और आधा इलाका बाहर निकाल दिया गया, चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया। तब यह सोच थी कि हरियाणा अपनी राजधानी, शायद रोहतक में बना लेगा और चंडीगढ़ केवल बाकी बचे पंजाब की राजधानी बना रहेगा। पर छह दशकों से मामला लटकता आ रहा है। चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने लिखा है, लाहौर छिन जाने के बाद चंडीगढ़ को सदा ही पंजाब की राजधानी के तौर पर देखा गया था जो सांस्कृतिक और भाषाई हकीकत है जिसे दूर नहीं किया जा सकता।

चंडीगढ़ को कभी भी केन्द्रीय शासित शहर के तौर पर सोचा नहीं गया था। यह पंजाब के लिए बनाया गया शहर है। जब 1966 में इसे यूनियन टैरिटरी बनाया गया तो यह अस्थायी प्रबंध था। वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने चंडीगढ़ का मामला चुपचाप बिना सलाह मशविरा किए तय करने की कोशिश की थी। प्रयास था कि कानून में संशोधन कर चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाया जाए जैसे दूसरे केन्द्रीय शासित प्रदेश हैं। संसद में इस आशय के लिए विधेयक लाने की तैयारी शुरू हो गई थी जिसे शोर मचने के बाद अब रद्द कर दिया गया है। अगर यह कानून बन जाता तो पंजाब का बचा खुचा सम्बन्ध भी टूट जाता और यह शहर बाकी यूटी की तरह ले.गवर्नर के अधीन आ जाता। 2016 में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। पंजाब के राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर प्रशासक लगाने का प्रयास किया गया जिसे अब की तरह वापिस लेना पड़ा था। यह कदम वापिस लेना समझदारी है। हैरानी है कि पंजाब के इतिहास और लोगों की संघर्षशील मानसिकता को समझने में इतनी भूल की गई। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आजकल भाजपा में हैं, ने भी शिकायत की है कि केन्द्र पंजाब को ठीक तरह से समझता नहीं। आज की स्थिति में पंजाब को छेड़खानी की नहीं मरहम की जरूरत है, जो नहीं लगाई जा रही। बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शिकायत है कि यह पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया और जो पैसा आया है वह भी सामान्य सरकारी योजनाओं का पैसा है जो बाढ़ न आती तो भी मिलता। केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कहना है कि 800 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। मुझे मालूम नहीं कि सही स्थिति क्या है, पर पंजाब में यह प्रभाव फैल गया है कि केंद्र सरकार अगर भेदभाव नहीं कर रही तो सहयोग भी नहीं कर रही। पंजाब सीमावर्ती प्रदेश है जहां पाकिस्तान साजिश करता रहता है।

सम्पादकीय...

जेन-जी...

भारत में जेन-जी कमाल कर रहा है। युवा उद्यमी कचरा प्रबंधन से निपटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसी ऐप बनाई गई है जो आम समस्या को एक व्यापक समाधान में बदल देता है। बेंगलुरु में एक युवा संस्थापक ने परम्परागत कार्य संरचना की दीवारों को चुनौती देते हुए फैशन प्लेटफार्म लॉन्च किया जो सफलता के झंडे गाड़ रहा है। कोई पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो कोई गांव में सौर ऊर्जा पहुंचा रहा है। जनरेशन जेड की प्रतिबद्धता का बदलाव लाने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का मिश्रण भी है। पिछले कुछ समय में पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल और कई अन्य देशों में युवाओं, विशेषकर जेन-जी वर्ग के बीच असंतोष और विद्रोह की लहरें उठीं। वहां बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और प्रशासनिक अक्षमताओं ने युवाओं को सड़क पर उतरने पर मजबूर किया। व्यवस्था परिवर्तन की मांग और हिंसक प्रदर्शन इन देशों में गहरी बेचैनी और अव्यवस्था के रूप में सामने आए। इस परिप्रेक्ष्य को भारत में भी कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां राजनीतिक रूप भुनाने का प्रयास कर रही हैं। वे युवाओं को उकसाने, भड़काने और भ्रमित करने की कोशिशों में लगी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से टूलकिट तैयार कर गलत जानकारियां फैलाना और नेताओं द्वारा गैर-जिम्मेदाराना बयान देना इसका उदाहरण है। यह प्रवृत्ति न केवल निंदनीय है, बल्कि अत्यंत चिंतनीय भी है, क्योंकि यह युवा शक्ति को उसकी रचनात्मक और राष्ट्र निर्माण की दिशा से भटकाने का कुत्सित प्रयास है। जब भारत के युवाओं, विशेष रूप से जेन-जी को लेकर विचार किया जाता है तब यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत की स्थिति इन देशों से भिन्न है। भारतीय युवा विशेषकर जेन-जी मूलतः राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत है। देश उनके लिए सर्वोपरि है। भारत के युवा की समझ पूरी तरह से विकसित है कि देश के निर्माण का मार्ग विद्रोह से नहीं, बल्कि नवाचार, परिश्रम और लोकतांत्रिक माध्यमों से निकलता है। यही कारण है कि भारतीय युवा अपने उद्यम, अथक परिश्रम और राष्ट्रभक्ति से हर क्षेत्र में भारत के ध्वज वाहक बने हुए हैं। भारत का युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान में इसरो की उपलब्धियों के पीछे युवा वैज्ञानिकों का योगदान है। कंप्यूटर और आईटी क्षेत्र में भारतीय युवा विश्व की दिग्गज कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। स्टार्टअप कल्चर का उभार भी इसी ऊर्जा का परिणाम है जिसने भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 से 7 सालों में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र बड़े बदलावों से गुजर रहा है और यह अब खुला, सहयोगी और नवाचार से प्रेरित अर्थतंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की ओर से अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा खासकर 'जेन जी यूथ' को भरपूर फायदा उठाने के अवसर मिले हैं। भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमताएं हैं और यह क्षमताएं केवल कुछ ही देश के पास है। हमारे पास कुशल इंजीनियर, उच्च गुणवत्ता उत्पादन अर्थतंत्र और विश्व के बेहतरीन प्रक्षेपण स्थल हैं। साथ ही नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला माइंड सेट भी है। भारत की युवा शक्ति को नवाचार और जोखिम उठाने वाली क्षमता तथा उद्यमिता से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इसके चलते आज विविध क्षेत्र में भारत नई बुलंदियों छू रहा है। स्काई रूट का इंफिनिटी कैंपस भारत की नई सोच नवाचार और युवा शक्ति का प्रतिबिंब है। उन्होंने स्काई रूट के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-एक का अनावरण भी किया। इसमें उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इस अत्याधुनिक केंद्र में बहु प्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन विकास एकीकरण और परीक्षण के लिए लगभग 20 हजार वर्ग फुट का कार्य क्षेत्र होगा तथा हर महीने का एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। जेन-जी के लिए कहा जाता है कि यह लगभग वर्ष 1995 से 2010 के बीच जन्मी ऐसी पीढ़ी है जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों के प्रयोग और सोशल मीडिया में सक्रिय रहती है। सर्वविदित है कि वर्ष 1990 का दशक वैश्विक पटल पर भूमंडलीकरण, बाजारवाद और तकनीक के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का समय था। परिणामतः इस दौर में जन्में बच्चे उस तकनीक से परिचित होकर विकासक्रम में आगे बढ़े। विक्रम-1 का निर्माण एक साधारण औद्योगिक उपलब्धि नहीं बल्कि इकोसिस्टम निर्माण का परिणाम है। स्काईरूट एयरोस्पेस का नया इंफिनिटी कैंपस हैदराबाद में दो लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में विकसित किया गया है, जहां रॉकेट डिजाइनिंग, डवलपमेंट, इंटीग्रेशन और परीक्षण की विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत पहली बार निजी तौर पर अपने लॉन्च वाहन निर्मित करने में सक्षम हुआ है। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, औद्योगिक रोजगार, वैश्विक निवेश और भारत के स्टार्टअप कल्चर के परिपक्व होने का संकेत भी है। भारतवर्ष भिन्न-भिन्न प्रकार की विविधताओं से संपन्न बड़ा देश है। यहां परंपरा और आधुनिकता, अध्यात्म, ज्ञान- विज्ञान और तकनीक सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहां कोई एक विचार अथवा तकनीक एकाएक सभी को समान रूप से अपना वर्चस्व नहीं बना सकते। भारत का जेन-जी आज 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में है। इस जेन- जी के भरोसे, संकल्प और भागीदारी से ही देश विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा है। यह जेन-जी ही भारत में नए-नए स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आकार दे रहा है। यह जेन-जी ही भारत की ताकत है। इसमें सृजनशीलता है, इसमें संघर्ष है, सपने हैं, संकल्प है और उन्हें पूरा करने के लिए पुरुषार्थ भी है। ये नए भारत की नींव के पत्थर हैं, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है। ये जितना ज्ञान-विज्ञान और तकनीक पर भरोसा करते हैं उतना ही भारत की ज्ञान परंपरा, संत-महापुरुष परंपरा एवं सनातन परंपरा पर इनका विश्वास है। भारत का जेन-जी न केवल अपने देश की अपितु विश्व के विभिन्न देशों में वहां की विभिन्न व्यवस्थाओं की धुरी बनता जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज बहुत से युवा तेजी से विश्व के बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नए-नए आविष्कार और उपलब्धियां हासिल करने वाली यह जेन-जी पीढ़ी ही है।

नाम का बवाल

2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक उपनाम पर तीखा प्रहार किया था। 17वीं लोकसभा के आम चुनावों से पहले गांधी ने मोदी के उपनाम पर टिप्पणी की थी- जो नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी से जुड़े थे। यह बयान कई मानहानि याचिकाओं का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। सूरत, गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को 'मोदी' समुदाय के पूरे वर्ग को बदनाम करने वाला बयान देने का दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें दो वर्ष की सजा सुनाई, जिसके साथ ही उनकी संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। कानून के प्रावधानों के अनुसार, संसद सदस्य उन मामलों में अयोग्य घोषित होते हैं जिनमें दोषसिद्धि के बाद दो वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है। गुजरात हाई कोर्ट में दायर अपील से भी राहत नहीं मिली। राहत अंततः सुप्रीम कोर्ट से मिली। गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस सजा के चलते गांधी अपने सार्वजनिक जीवन के आठ महत्वपूर्ण वर्ष खो देंगे। उल्लेखनीय है कि कानून के तहत किसी व्यक्ति को कारावास पूरा करने के बाद छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोका जाता है। सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि केरल के वायनाड के मतदाता जो 2019 से गांधी की लोकसभा सीट है, उनके अयोग्य होने से अचानक बिना प्रतिनिधित्व के रह गए। यदि ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रहती तो कांग्रेस नेता आगामी चुनावों में भी भाग नहीं ले पाते। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हालांकि टिप्पणी की कि गांधी की बातें असभ्य और अप्रिय थीं, पर दो साल की सजा योग्य नहीं थीं। गांधी को राहत मिल गई, पर उनके वकील सिंघवी के लिए यह मामला कई रातों की बेचैनी लेकर आया। उतना ही सच यह भी है कि गांधी को राहत दिलाने में सिंघवी की कानूनी कुशलता निर्णायक रही। सिंघवी ने स्वयं कहा कि यदि यह मामला हार गया होता तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने सार्वजनिक जीवन के आठ महत्वपूर्ण वर्ष राजनीति से बाहर बिताते- इसके नतीजे बेहद गंभीर होते। ट्रायल और अपीलीय अदालतों में मामला हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो मैंने राहुल जी से कहा कि मैं रोज मामले लड़ता हूं, पर आपके मामले ने मुझे कई रातें सोने नहीं दिया। यह बहुत व्यक्तिगत-सा लग रहा था। सिंघवी ने गांधी से यह भी कहा कि कांग्रेस के भीतर और बाहर कई लोग उनके असफल होने की प्रतीक्षा में हैं। इस पर गांधी ने जवाब दिया परिणाम भूल जाइए। हारेंगे तो हारेंगे, आप बस दलील रखिए और सिंघवी ने वही किया पूरी ताकत से। सिंघवी स्वयं को श्रेय देने में संकोच करते हैं लेकिन सच यह है कि यदि आज राहुल गांधी संसद में बैठकर भाजपा का सामना कर रहे हैं तो इसका बड़ा हिस्सा सिंघवी की भूमिका का ही परिणाम है। कानून के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वाले सिंघवी ने लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए मुकदमे लड़े हैं सिवाय भाजपा के, जो उनसे मानो दूर ही रहती है।

खुद सिंघवी कहते हैं, शरद पवार से लेकर स्टालिन, अखिलेश यादव, ममता और अभिषेक बनर्जी और आप के अनेक नेताओं से लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं तक मैंने सभी के लिए काम किया है। मैं पूरी ईमानदारी से मानता हूं कि मुझे भाजपा के लिए भी पेश होना चाहिए, पर आज की राजनीति में यह संभव नहीं है। पहले के जमाने में यह होता था।

अगर आपको दांत में दर्द है तो क्या आप अच्छे दंत चिकित्सक ढूंढेंगे या फिर भाजपा-कांग्रेस दंत चिकित्सक में से चुनेंगे? वे दोहराते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे भाजपा के लिए पेश न हों। भाजपा के लोगों से उन्हें मामले मिलते भी हैं, लेकिन तब मुझे विनम्रता से मना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी नीयत पर सवाल खड़े होने का डर रहता है। हालांकि, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन का मामला उनके लिए अलग था। सोरेन तो तब रो पड़े जब सिंघवी ने अचानक उनका केस छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए जाने की संभावना जताई गई थी। चूंकि मामला गड़बड़ किस्म के भ्रष्टाचार से जुड़ा था, मैंने उचित समझा कि हट जाऊं। यह गलत निर्णय था, क्योंकि नियुक्ति कई महीने बाद हुई, सिंघवी कहते हैं। सोरेन के लिए तो जैसे आसमान टूट पड़ा आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सिंघवी से कहा। यह 1996 की बात है। कानूनी पक्ष से इतर, सिंघवी को जिन बातों ने आदिवासी समुदाय के करीब रखा, वह थी उनकी सरलता। आदिवासी बेहद सरल दिल के लोग होते हैं। बिना किसी आडंबर के आते, फटे-पुराने कपड़ों और चप्पलों में। तब कई के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं होते थे। वे साफ बताते कि कितना दे सकते हैं और मैं कह देता ठीक है, मैं आपका केस लड़ूंगा। सबसे महत्वपूर्ण यह कि वे बहुत ईमानदार थे, कई अन्य वादकारियों के विपरीत। उन्होंने कहा हमने ये किया था क्योंकि हमें सरकार का समर्थन करना था। कोर्ट में मैंने उनके लिए अच्छा किया, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा। सिंघवी मानते हैं, गलती मेरी थी। कोई कारण नहीं था कि मैं उनका केस न लड़ता, मेरी नियुक्ति तो आठ महीने बाद हुई। एक बेहद मांग वाले वकील के रूप में सिंघवी के पास प्रभावशाली और ईर्ष्या-योग्य मुकदमों की लंबी सूची है ऐसी, जिनके लिए कई वकील बहुत कुछ देने को तैयार हों। उनमें से एक अब भी चर्चा में रहता है सांबा जासूसी मामला। यह तब की बात है जब मैं एएसजी था सिर्फ 37 वर्ष की उम्र में। यह बड़ा सीखने का दौर था क्योंकि जब आपके सामने सोलि सोराबजी और फली नरीमन जैसे दिग्गज हों तो हाथ कांपते हैं, और समझ आता है कि आपका सबसे बड़ा साथी वही घंटे हैं जो आपने पिछली रात मेहनत में लगाए थे। जहां तक उस मामले का सवाल है, वह कुछ कुख्यात सा था, क्योंकि वह देशविरोधी जासूसी जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा था। मुझे दमदार पक्ष रखना पड़ा। तर्क-वितर्क के चरण में मैं मौजूद था लेकिन मामला मेरे कार्यकाल में समाप्त नहीं हुआ।

पुतिन-आपका स्वागत है

यह गाना मास्को वासियों में इतना प्रख्यात हुआ कि राजकपूर को अंततः रूस जाना पड़ा और लाल टोपी पहन कर जब वह शहर में घुसे तो एक समां ही बंध गया। रूस तब सोवियत संघ कहलाता था। कालांतर में भारत और सोवियत संघ के रिश्ते इतने प्रगाढ़ हुए कि भारत-पाक युद्ध के दौरान जब भारत के वीर जवानों ने अमेरिकी पैटेंट टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया और पाकिस्तान को दिए गए सैबर जैटों को हमारे नेट विमानों ने दिन में तारे दिखा दिए तो जिस ढंग से रूस की मदद से भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। उसका कोई जवाब नहीं है। असल दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। भारत-रूस संबंधों का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अतीत में भारत पर जब-जब मुसीबतें आईं तब-तब रूस ने हमारा साथ दिया। कौन नहीं जानता कि 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए अपना सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने का फैसला किया तब सोवियत संघ ने भारत की मदद के लिए अपना विध्वंसक बेड़ा भेज दिया था। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल भी भारत के हक में किया। 1971 में ही भारत और सोवियत संघ ने एक शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए जिससे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग मजबूत हुआ। रूस ने भारत को सैन्य प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक सहयोग दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2021 में भी नई दिल्ली आए थे। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति संबंधों के सम्पूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए हर साल एक शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं। अब तक दोनों देशों में 22 शिखर वार्ताएं हो चुकी हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मास्को गए थे। अब एक बार फिर दो दोस्तों का मिलन हो रहा है। विश्व के दो नेता पुतिन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोनों नेता विश्व व्यवस्था बदलने की क्षमता रखते हैं। पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत-रूस से कच्चे तेल की खरीद रोकने के लिए अमेरिकी दबाव का सामना कर रहा है। रूस से हथियार खरीदने पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत से चिढ़े बैठे हैं। ट्रंप ने भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगा रखा है। दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध जारी रहने से रूस पश्चिमी देशों के दबाव में है। यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की कमाई को निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पुतिन की वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इस बैठक को लेकर ट्रंप और पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेनाध्यक्ष मुनीर तनाव में हैं। भारत दौरे पर आने से पहले ही रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने भारत के साथ रक्षा भागीदारी को लेकर एक सैन्य समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर भारत और रूस की सहमति बनी तो रूस के 5 युद्ध पोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। साथ ही भारत के इतने ही सैनिक और युद्ध पोत रूसी जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। रूसी संसद ने रेलोस यानि इंडिया-रूस रेसीप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते के तहत इसकी मंजूरी दी है। रेलोस डील से दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन ने कुछ दिन पहले ही आदेश दिया है कि रूस भारत द्वारा कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात किए जाने के कारण पैदा हुए व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए कदम उठाएगा।

वैश्विक शक्ति- समीकरण के केंद्र में भारत-रूस की नई साझेदारी

वैश्विक स्तरपर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 23 वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, 4-5 दिसंबर 2025 की भारत यात्रा न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन के संदर्भ में भी अत्यंत निर्णायक मानी जा रही है। वर्ष 2022 में यूक्रेन संघर्ष आरंभ होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा है, इसलिए पूरी दुनियाँ की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी है। भारत और रूस के ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध दशकों से अटूट रहे हैं, किंतु इस बार की यात्रा कई नए आयाम खोलने वाली मानी जा रही है जो 21वीं सदी के भू- राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत और रूस के संबंध सदैव समानता, सम्मान और पारस्परिक विश्वास पर आधारित रहे हैं। सामरिक हथियारों,ऊर्जा आपूर्ति,अंतरिक्ष तकनीक नागरिक परमाणु सहयोग तथा रक्षा उत्पादन में दोनों देशों की साझेदारी दुनिया के बड़े रणनीतिक गठबंधनों की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और दीर्घकालिक साबित हुई है। पुतिन की इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य इन साझेदारियों को आधुनिक वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्गठित करना तथा आने वाले दशकों के लिए व्यापक सहयोग का नया मार्ग तैयार करना है। विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा, आर्कटिक सहयोग,समुद्री संपर्क,डिजिटल मुद्रा-प्रणाली और रक्षा नवाचारों में दोनों देशों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ताएँ होने की संभावना है। आज जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवीय संरचना की ओर तेजी से बढ़ रही है,भारत और रूस दोनों ही इस नए वैश्विक क्रम में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। भारत एक ओर अमेरिका, यूरोपीय संघ और क्वाड देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है,वहीं दूसरी ओर रूस उसके सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदारों में बना हुआ है। इसी कारण पुतिन की यह यात्रा भारत के मल्टी-अलाइनमेंट दृष्टिकोण को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह यात्रा यह भी दर्शाती है कि भारत वैश्विक कूटनीति के भीतर एक सेतु-राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने में सक्षम है।यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार- व्यवस्था को बदल दिया है। ऐसे समय में भारत की भूमिका रूस के लिए अत्यधिक महत्व की हो गई है। ऊर्जा आपूर्ति, वैकल्पिक भुगतान-प्रणाली, समुद्री मार्गों के विकास और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ संवाद में भारत रूस का प्रमुख सहयोगी बनकर उभरा है। पुतिन की यात्रा इस सहयोग को एक नई संस्थागत मजबूती देने का अवसर प्रदान करती है। विशेषकर रुपए-रूबल व्यापार,अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे और सुदूर-पूर्व रूस में भारतीय निवेश जैसे मुद्दे इस यात्रा के केंद्र में रहने की संभावना रखते हैं। साथियों बात अगर हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को समझने की करें तो,पुतिन की यह राजकीय यात्रा कई मायनों में खास होगी,यह भारत और रूस, दोनों के नेतृत्व को अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने,विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दृष्टिकोण निर्धारित करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी।कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस और भारत अपनी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों (नेशनल पेमेंट सिस्टम) को जोड़ने के इच्छुक है और दिसंबर में जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली का दौरा करेंगे तो यह विषय एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। भारत और रूस के बीच पुराने और मजबूत संबंध दुनियाँ जानती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। यूक्रेन युद्ध, बदलती वैश्विक राजनीति, डिफेंस डील्स और भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका-इन सबके बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण सटीक मायने रखता है। साथियों बात अगर हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा की विशेषता का विश्लेषण करें तो, यह यात्रा कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है।

यह 23वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है,जो इस दीर्घकालिक साझेदारी की निरंतरता का प्रतीक है। यूक्रेन संघर्ष के बाद पुतिन का भारत आना यह भी दर्शाता है कि रूस भारत को एक विश्वसनीय,तटस्थ और प्रभावशाली साझेदार के रूप में देखता है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को आधुनिक वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्जीवित करना है। बदलते आर्थिक तंत्र, तकनीकी प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा,रक्षा आधुनिकीकरण और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कीवास्तविकताओं को देखते हुए दोनों देशों के लिए यह बैठक नई संभावनाओं और नए समझौतों का मार्ग खोल सकती है। (1) रक्षा सहयोग- रणनीतिक सुरक्षा की पुनर्पुष्टि -मोदी वार्ता में रक्षा सहयोग मुख्य केंद्र में रहने की संभावना है। भारत अपनी वायु रक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के लिए रूस से अतिरिक्त एस-400 वायु-रक्षा रेजिमेंट प्राप्त करने पर विचार कर सकता है। साथ ही, लड़ाकू विमानों,मिसाइल प्रणालियों हेलीकॉप्टरों और उन्नत सैन्य तकनीकों के संयुक्त उत्पादन पर गंभीर विमर्श संभावित है। भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना चाहता है, और रूस इस दिशा में एक प्रमुख साझेदार बना रह सकता है। पुराने रक्षा प्लेटफार्मों जैसे सु-30एम केआई के उन्नयन, भविष्य की प्रणालियों जैसे एस-500 तथा अन्य उन्नत एंटी-मिसाइल प्रणालियों पर भी चर्चा संभव है। यह सहयोग भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए अनिवार्य है।(2)आर्थिक, ऊर्जा और औद्योगिक साझेदारी- इस यात्रा के आर्थिक आयाम अत्यंत व्यापक है। दोनों देश एक व्यापक 2030 रणनीतिक आर्थिक रोडमैप को अंतिम रूप दे सकते हैं,जिसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष, कृषि, खनन और औद्योगिक सहयोग शामिल हो सकते हैं। रूस भारत को कच्चे तेल, एलएनजी, कोयला तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालीन प्रस्ताव दे सकता है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में सहयोग भी भविष्य के ऊर्जा विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। दूसरी ओर, भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए रूस को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत तथा निवेश साझेदार के रूप में देखता है। औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी साझेदारी से दोनों देशों के हितों को समान रूप में लाभ मिल सकता है।

(3) भुगतान प्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता-इस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू दोनों देशों की राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों- भारत की रु-पे और रूस की एम आईआर को जोड़ने का प्रस्ताव है। यह कदम दोनों देशों को पश्चिमी वित्तीय तंत्र, विशेषकर स्विफ्ट, से आंशिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है।इससे पर्यटकों व्यवसायियों और छात्रों को लेन-देन में सीधी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही रुपया-रूबल व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यद्यपि इस प्रक्रिया की तकनीकी और नियामकीय चुनौतियाँ कम नहीं, फिर भी यह पहल दोनों देशों के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता का मार्ग खोल सकती है। (4) कुशल मानव संसाधन और श्रम सहयोग-रूस ने भारत से कुशल और अर्द्ध- कुशल श्रमिकों की भर्ती में रुचि व्यक्त की है। यह प्रस्ताव रूस की श्रम-गत आवश्यकता और भारत के विशाल युवा जनसंख्या व कौशल क्षमता का सम्मिलित समाधान प्रस्तुत करता है। पुतिन-मोदी वार्ता में प्रवासन, वीज़ा व्यवस्था, कौशल मान्यता और पारस्परिक रोजगार प्रणालियों पर समझौते होने की संभावना है। यह कदम भारत के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के नए अवसर खोल सकता है। (5) अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भू-राजनीतिक संदेश-यह यात्रा दोनों देशों के लिए विश्व मंच पर एक संदेश भी है। पश्चिमी प्रतिबंधों और भू- राजनीतिक दबावों के बीच रूस भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर अपनी रणनीतिक स्थिति को स्थिर करना चाहता है। वहीं भारत, अमेरिका और यूरोप से निकट संबंध बनाए रखते हुए भी रूस जैसेपारंपरिक साझेदार के साथ संतुलन कायम रखना चाहता है। भारत का लक्ष्य स्पष्ट है-बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखना। यह यात्रा इसी उद्देश्य को और मजबूती प्रदान कर सकती है। (6) चुनौतियाँ और संवेदनशील मुद्दे- यद्यपि यह यात्रा अवसरों से भरपूर है। चुनौतियाँ भी समान रूप से मौजूद हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए रूस के साथअत्यधिक निकटता पश्चिम की प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है। भुगतान प्रणाली, मुद्रा समन्वय, तकनीकी हस्तांतरण और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अड़चनें भी कम नहीं।इसके अतिरिक्त, यूक्रेन संघर्ष का वैश्विक राजनीतिक प्रभाव, रूस पर जारी प्रतिबंध,और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में बाधाएँ भी भारत -रूस सहयोग की गति को प्रभावित कर सकती हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दिसंबर 2025 की पुतिन-भारत यात्रा भारत-रूस साझेदारी के लिए एक निर्णायक क्षण है। यह दौरा केवल पुरानी मित्रता की पुनर्पुष्टि नहीं,बल्कि बदलती वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप संबंधों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक गंभीर प्रयास है रक्षा ऊर्जा अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली,मुद्रा समन्वय, मानव संसाधन और अंतरिक्ष सहयोग-इन सभी क्षेत्रों में संभावित समझौते आने वाले वर्षों के लिए साझेदारी की नई संरचना तैयार कर सकते हैं। चुनौतियाँ अवश्य हैं, परंतु अवसर भी उतने ही बड़े हैं। यदि दोनों देश इन अवसरों को व्यावहारिक और संतुलित नीति के साथ पकड़ पाते हैं,तो भारत-रूस संबंध आने वाले दशक में वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा का निर्धारण कर सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सायं पंचशिला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/38882)

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2025 की गूंज पहुंची विश्व के कोने-कोने तक अदभुत और अनोखी शिल्पकला के साथ देश-प्रदेश की लोक संस्कृति ने ब्रह्मसरोवर के तटों को दी नई पहचान

चंडीगढ़।

कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के पावन तट 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज विश्व के कोने-कोने तक पहुंची। इस गूंज के साथ ही महोत्सव ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। इस महोत्सव में अद्भुत शिल्पकला के साथ-साथ देश-प्रदेश की लोक संस्कृति ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गूंज विदेशों में भी सुनाई दी, यहां पर आने वाला प्रत्येक पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गाथा को भुला नहीं पा रहा है और इन अनोखे पलों को दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों के साथ-साथ लाखों श्रद्धालु अपने कैमरों में कैद कर रहे है। इस महोत्सव की अनोखी छटा अपने आप में लोक संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां एक ओर शिल्पकारों की अद्भुत और आश्चर्य चकित करने वाली शिल्पकला ने लोगों को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर किया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों की अलग-अलग

***महोत्सव को सफल बनाने में शिल्पकारों, कलाकारों व पर्यटकों का रहा अहम योगदान**

***शिल्पकला और लोक संस्कृति के अनोखे झरोखों के साथ महोत्सव का हुआ समापन**

वेशभूषा की लोक संस्कृति ने लोगों के मन को मोह लिया है और इस भव्य आयोजन के लिए लोग सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते नजर आए। धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर आने वाले पर्यटकों ने इस महोत्सव की हर क्षणों का लुफ्त उठाया। इस भव्य आयोजन में विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति ने महोत्सव की फिजा में इंद्रधनुष के रंग भरने का काम किया है। शिल्प कला और संस्कृति के यादगार लम्हों को अपने जीवन के हसीन क्षण बनाने के लिए हरियाणा ही नहीं भारत वर्ष से लोग कुरुक्षेत्र की तरफ अग्रसर हुए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन भारी संख्या में पर्यटक महोत्सव का आनंद लेने के लिए पहुंचे। अहम पहलू यह है कि सरस और शिल्प मेले में शिल्पकारों ने अच्छा व्यवसाय किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-2025 के तमाम क्षणों को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है। इस महोत्सव को अगर देश की संस्कृति और शिल्पकला का केन्द्र बिन्दू कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस महोत्सव के शिल्प मेले में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केन्द्र पटियाला की तरफ से विभिन्न राज्यों के शिल्पकार पहुंचे है। इनमें से कई शिल्पकारों को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय के साथ-साथ अन्य अवार्ड मिल चुके है। इन शिल्पकारों की शिल्पकला को निहारने के लिए रोजाना भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे।

महोत्सव में आए शिल्पकारों से बातचीत कर आंकलन किया गया तो शिल्प और सरस मेले में अच्छा व्यवसाय हो चुका है। इन आंकड़ों से सहजता से आंकलन किया जा सकता है कि यह महोत्सव शिल्पकारों के लिए आर्थिक रूप से भी एक विशेष महोत्सव के रूप में पहचान बना चुका है।

***विभिन्न प्रदेशों की लोक संस्कृति और वेशभूषा ने मोहा पर्यटकों का मन**

ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर लगे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों की अलग-अलग वेशभूषा और लोक संस्कृति ने लोगों के मन को मोह लिया है। इतना ही नहीं स्थानीय लोगों के साथ-साथ अन्य पर्यटकों ने भी इस अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की यादों को अपने-अपने प्रदेशों में जाने के बाद साझा करने का काम किया। बच्चे, बुर्जुग और महिलाओं के साथ-साथ युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हर कोई इस महोत्सव की जमकर प्रशंसा कर रहा है।

***हरियाणवी खान-पान के साथ पंजाब और राजस्थानी व्यंजनों का भी उठाया लुफ्त**

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां एक ओर ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर लगे सरस और क्राफ्ट मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर आने वाले पर्यटकों ने हरियाणवी खानपान के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुफ्त उठाया। इस भव्य आयोजन में जहां शिल्पकारों ने अपनी शिल्पकला से लोगों को प्रभावित किया है वहीं दूसरी ओर पर्यटक विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों को भी पसंद किया।

***संध्या कालीन आरती के साथ-साथ पर्यटक रंग बिरंगी लाइटों का आनंद लेते आए नजर**

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर होने वाली संध्या कालीन आरती में जहां पर्यटकों ने भाग लिया, वहीं दूसरी ओर रात्रि के समय में पर्यटक इस भव्य आयोजन में रंग बिरंगी लाइटों से सजे ब्रह्मसरोवर के तट का आनंद लेते हुए नजर आए। पवित्र ग्रंथ गीता पूरी दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना-समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है।

हम अपने जीवन और उसके उदेश्यों को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते है, लेकिन यह पवित्र ग्रंथ हमें इन प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देता है।

यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। इस ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम सांध्यकालीन महाआरती ने किया।

करनाल में 162 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है यूनिटी मॉल

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के लिए होगा राष्ट्रीय स्तर का मंच

मुख्य सचिव ने की परियोजना की प्रगति की समीक्षा

चंडीगढ़। हरियाणा के करनाल में बनने जा रहा यूनिटी मॉल पूरे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) उत्पादों, विशेषकर 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पहल के अंतर्गत तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच का काम करेगा। शहर की औद्योगिक सम्पदा के सेक्टर-37 में ग्रांड ट्रंक रोड के साथ 162.88 करोड़ रुपये की लागत से 3.87 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस मॉल को जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां, करनाल में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल परियोजना तथा फरीदाबाद और गुरुग्राम में बनाए जा रहे दो वर्किंग वूमेन हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि परियोजना का खुदाई कार्य तीव्र गति से जारी है, जो निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्माण की स्वीकृत समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने तथा कार्य की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए। यह परियोजना केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से विकसित की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित इस परियोजना स्थल से दिल्ली और चंडीगढ़ समेत अन्य प्रमुख उत्तरी शहरों से भी बेहतरीन कनैक्टिविटी है। करनाल के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्र के तौर पर उभरने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति से इस परियोजना के व्यापक आर्थिक प्रभाव को और मजबूती मिलेगी। इस यूनिटी मॉल को देशभर के एमएसएमई उत्पादों-विशेषकर 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' श्रेणी के उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमियों की मार्केटिंग लागत कम होगी, घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में उनकी पहचान बढ़ेगी और नए व्यावसायिक सहयोग के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य दहिया ने बताया कि यह यूनिटी मॉल राज्य के विशिष्ट उत्पादों के स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, बिजनेस-टू-बिजनेस नेटवर्किंग हब तथा पर्यटन आकर्षण के रूप में भी कार्य करेगा, जो देश की विविध विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। यह परियोजना केंद्र सरकार के स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने, बाजार पहुंच बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले अवसंरचना तंत्र के माध्यम से अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने की नीति से पूरी तरह मेल खाती है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने एचएसआईआईडीसी और एमएसएमई निदेशालय को सुचारू एवं प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रारम्भिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने और परियोजना की गति बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूनिटी मॉल हरियाणा के आर्थिक भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है, और सरकार इसे समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए एनरोलमेंट की तिथियां निर्धारित

चंडीगढ़।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सभी विद्यालय मुखिया हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी एनरोलमेंट शुल्क के साथ 08 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात 300 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 21 दिसंबर से 28 दिसम्बर तथा 1000 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 29 दिसंबर, 2025 से 05 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों के विवरणों में 06 जनवरी से 08 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की एनरोलमेंट रिटर्न/शुल्क एक बार में (एकमुश्त) ऑनलाइन भरी जानी है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी

विद्यालय 8 दिसम्बर से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

विद्यार्थी का आवेदन फार्म ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यालय द्वारा दाखिला खारिज रजिस्टर में अन्तिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है। बोर्ड प्रवक्ता ने आगे बताया कि कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों का 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट की अन्तिम तिथि के बाद प्रश्न-पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार शुल्क जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है और उन द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से नियमित/मुक्त विद्यालय के तौर पर न देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की है तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11वीं में जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पहले ही हो चुका है ऐसे विद्यार्थी का विद्यालयों द्वारा पुनः रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100/-रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाया जाना है उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं, 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं या दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया है उनके एनरोलमेंट फॉर्म दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है केवल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रूपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा। उन्होंने स्कूलों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न भरते समय विद्यार्थी के आधार नम्बर के साथ-साथ पिता का आधार नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य है, यदि किसी कारणवश पिता का आधार नंबर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें।

इस बार एनरोलमेंट रिटर्न के दौरान परीक्षार्थियों की APAR ID का कॉलम भी दिया गया है, जिसमें परीक्षार्थियों की APAR ID संख्या दर्ज की जानी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जो फोटो आवेदन-पत्र में भेजे जाने हैं, वह विद्यालय की वर्दी में ही हों, जिससे यह अलग पहचान हो सके कि अमुक परीक्षार्थी अमुक विद्यालय का है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि विद्यालयों द्वारा एनरोलमेंट ऑनलाइन पार्टल पर आवेदन फार्म भरते समय अन्य राज्य से आने वाले विद्यार्थियों की प्रतिहस्ताक्षरित एसएलसी/टीसी एवं कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का 10वीं का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा एनरोलमेंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरान्त उनमें केवल दो त्रुटियों (जन्म तिथि को छोड़कर) को बिना शुल्क तथा दो से अधिक त्रुटियां पाए जाने पर 300 रूपये प्रति शुद्धि शुल्क सहित निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। इसके उपरान्त बोर्ड कार्यालय में मूल रिकार्ड व वांछित सत्यापित प्रतियों सहित 30 -रूपये शुल्क के साथ त्रुटियों में ऑफलाइन संशोधन करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विद्यालय अपने विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न आवेदन-पत्र उपरोक्त तिथियों में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना सुनिश्चित करें। विद्यालय एनरोलमेंट के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए बोर्ड कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र/अभिभावक को ना भेजें। ऑनलाइन रिटर्न भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हेल्पलाइन दूरभाष नम्बर 01664-254300, 254302, एवं दूरभाष नम्बर 01664-244171 से 176 E&t.164 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-मेल-asenr@bseh.org.in पर मेल भेजी जा सकती हैं।

दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने की ओर एक और कदम, सड़कों पर लगे खंभों से हो रही पानी की बौछार

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है आलम यह है कि ITO–विकास मार्ग पर लगाए गए कम्पनयुक्त पानी छिड़काव पोल प्रदूषण कम करने के प्रयासों को तेज करने के संकेत दे रहे हैं। 5 दिसंबर शुक्रवार सुबह आनंद विहार में एक्यूआई 347 और ITO पर 320 रिकॉर्ड किया गया, जिससे शहर को 'बेहद खराब' श्रेणी में बनाए रखा। यह स्थिति गंभीर है क्योंकि धुंध की मोटी परत ने आसमान को ढक लिया है और संसद में भी इस मुद्दे को लेकर तीखा विरोध देखने को मिला।

संसद में कई सांसद कर रहे प्रदर्शन

राजधानी के विकास मार्ग पर स्थापित पानी छिड़काव पोल धूल और हवाई कणों को नीचे बैठाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। CPCB की श्रेणी के अनुसार 301-400 एक्यूआई 'बेहद खराब' और 401-500 'गंभीर' माने जाते हैं, ऐसे में मौजूदा प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। पीटीआई के अनुसार, संसद में कई सांसद मास्क पहनकर और ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते दिखे। इसी बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को 'युद्ध स्तर पर' पर निपटने का ऐलान किया और ITO के मिस्ट स्प्रे सिस्टम का निरीक्षण कर इसकी तकनीकी क्षमता का जायजा लिया. उनके साथ मंत्री अशोक सूद और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

नागरिकों से ऐप पर शिकायतें दर्ज करने की अपील

मुख्यमंत्री ने बताया कि एनडीएमसी क्षेत्रों में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम मिलने के बाद नौ प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर इसी तरह के सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिन्हें बाद में पूरे शहर में विस्तारित किया जाएगा. 300 से अधिक मिस्ट स्प्रे यूनिट्स हाई-ट्रैफिक स्थानों पर लगाई जाएंगी. नागरिकों से एमसीडी-311 ऐप पर शिकायतें दर्ज करने की अपील की गई है, जिन्हें 72 घंटे में निपटाने की गारंटी दी गई है। वहीं, उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना और मुख्यमंत्री ने लोक निवास में बैठक कर अधिकारियों को धूल नियंत्रण, मलबा हटाने और रीजनल समीक्षा के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट और फिर तीन दिनों तक 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है। आगामी दो दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे, जबकि आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और 5 से 10 दिसंबर के बीच रात में धुंध तथा सुबह में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। उधर, मुंबई में बिगड़ते एक्यूआई ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। बोर्ड ने पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने पर मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 19 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद कर दिए हैं, जहां निरीक्षण में अपर्याप्त धूल नियंत्रण, उत्सर्जन प्रबंधन और अनुमति संबंधित खामियां पाई गईं।

4 दिन में 1200+ फ्लाइट रद्द, सरकार बैकफुट पर

वीकली रेस्ट नियम तत्काल वापस; देशभर में इंडिगो पैसेंजर 4 दिनों से परेशान, मारपीट के हालात

■ देशभर के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द या देरी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही हैयात्री तीन दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उन्हें दूसरी एयरलाइन की ऊंची टिकट कीमतें सामना करना पड़ रहा हैयात्रियों को सही जानकारी नहीं मिल रही है जिससे वे अपने जरूरी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

फ्लाइट रद्द का मुद्दा पहुंचा संसद, यात्रियों के साथ विपक्ष के निशाने पर भी आई इंडिगो, उठाए ये सवाल

■ आज आधी रात से नॉर्मल हो जाएंगी इंडिगो की फ्लाइट- एविएशन मिनिस्ट्री

■ इंडिगो ने अटका दिया : यात्रियों का बुरा हाल, किराए की दोहरी मार, दिल्ली-पटना 40 हजार तो दिल्ली-रांची 60 हजार किराया

नई दिल्ली।

इंडिगो का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके है कि रोजाना सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही है, जिससे यात्रियों को भारी नुकसान और परेशानी झेलनी पड़ रही है। बढ़ती शिकायतों के बाद डीजीसीए ने भी इंडिगो के अधिकारियों को तलब कर स्थिति पर चर्चा की है। लगातार हो रहे फ्लाइट कैंसिलेशन अब संसद में भी उठ गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले में सरकार को घेरा है। जबकि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इंडिगो परिचालन संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को देरी, उड़ानों के रद्द होने और असहाय महसूस करने के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच-फिक्सिंग वाले एकाधिकार का।

वहीं विपक्षी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पत्र में लिखा कि राज्यसभा के नियम 180 के तहत वे नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान इस गंभीर सार्वजनिक मुद्दे की ओर दिलाना चाहती हैं। ये मुद्दा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हजारों यात्री फंस गए, हवाई अड्डों पर संचालन प्रभावित हुआ और ऐसी घटनाएं बार-बार होने से यह संकेत मिलता है कि तत्काल सरकारी हस्तक्षेप, जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जरूरत है. ऐसे में मैं अनुरोध करती हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर शीघ्र बयान दें।

अपने पत्र में प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा

बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई।
देशभर में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कई उड़ानों में 7 घंटे तक की देरी हुई, 70 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित कई बड़े एयरपोर्ट प्रभावित हुए।
क्रू की कमी और परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण स्थिति और खराब हुई।
घरेलू मार्गों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित रहीं, जैसे मुंबई-इस्तांबुल रूट
एयरलाइन ने तकनीकी समस्याओं, एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ और परिचालन जरूरतों को इसकी वजह बताया।
ये स्थिति एयरलाइन की तैयारी, नियामक निगरानी और यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है

इस बीच शुक्रवार को इंडिगो की स्थिति और बिगड़ गई है। पूरे देश में अब तक 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और कई फ्लाइट्स घंटों लेट चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेले 220 से ज्यादा उड़ानें, बेंगलुरु में 100 से अधिक और हैदराबाद में 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। अन्य शहरों में भी भारी देरी देखी गई है। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि ठंड, धुंध और भारी भीड़ के बीच क्रू की कमी ने हालात को और खराब कर दिया है। एयरलाइन के मुताबिक, ऑपरेशंस को सामान्य करने में अगले 2-3 दिन और लगेंगे, और तब तक कई उड़ानें रद्द होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि, इंडिगो ने कहा है कि वह 8 दिसंबर से अपनी उड़ानों की संख्या कम करेगी, ताकि शेड्यूल स्थिर हो सके और कैंसिलेशन कम हो।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक्शनः इंडिगो के संकट पर तत्काल उपाय, विमानन कंपनी ने पूर्ण रिफंड की पेशकश

नई दिल्ली।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों, विशेष रूप से इंडिगो को, उड़ान कार्यक्रमों में गंभीर व्यवधान को दूर करने और बिना किसी देरी के सेवाओं को स्थिर करने के लिए तत्काल उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। जनता को होने वाली समस्याओं का समाधान करने और विशेष रूप से इंडिगो पर सेवा स्थिरता बहाल करने के लिए दो आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है, उम्मीद है आज आधी रात तक सभी उड़ान कार्यक्रम स्थिर हो जाएंगे और सामान्य होने लगेंगे; अगले कुछ दिनों में पूर्ण सेवाएँ और स्थिरता वापस आ जानी चाहिए; यात्री इंडिगो और अन्य द्वारा स्थापित सूचना प्रणाली के माध्यम से घर बैठे देरी, यदि कोई हो, पर नज़र रख सकते हैं; उड़ान रद्द होने की स्थिति में इंडिगो टिकटों के लिए स्वचालित रूप से पूर्ण धनवापसी सुनिश्चित करेगा। आदेश में आगे कहा गया है कि अगर यात्री कहीं फंस जाते है, तो उन्हें उन होटलों में ठहराया जाएगा जहाँ एयरलाइनों ने आवास बुक किया है। वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष उपाय किए गए हैं। उन्हें लाउंज की सुविधा प्रदान की जाएगी; विलंबित उड़ानों के यात्रियों को जलपान और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान की जाएँगी; नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक 24×7 नियंत्रण कक्ष समय-समय पर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सतर्क है और सभी हितधारकों के साथ लगातार परामर्श कर रही है। बयान में आगे कहा गया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा शुक्रवार को घोषित नियमों में छूट सहित, उड़ानों के समय को बहाल करने और जनता की समस्याओं को कम करने हेतु स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएँगे। पूरे भारत में चल रही उड़ानों के व्यवधान के बीच, इंडिगो ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 5 से 15 दिसंबर के बीच रद्द की गई सभी उड़ानों के लिए पूर्ण धनवापसी की पेशकश करेगी, जो भुगतान के मूल तरीके से स्वचालित रूप से संसाधित हो जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में, एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसने इस अवधि के दौरान रद्दीकरण या पुनर्निर्धारण पर पूरी छूट प्रदान की है और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए, हवाई अड्डों पर भोजन और नाश्ते के साथ-साथ हजारों होटल के कमरे और भूतल परिवहन विकल्पों की व्यवस्था की गई है। इससे पहले आज, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान संचालन को स्थिर करने और यात्रियों की परेशानी को कम करने में मदद के लिए इंडिगो एयरलाइंस को विशिष्ट क्रू ड्यूटी नियमों से एक बार की अस्थायी छूट प्रदान की। नियामक ने कहा कि यह छूट 0000-0650 बजे तक नाइट ड्यूटी के प्रावधानों और संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नागरिक उड्डयन आवश्यकताएँ धारा 7 श्रृंखला J भाग III संशोधन 2, चरण-II के तहत रात्रि संचालन पर प्रतिबंधों को कवर करती है, जो एयरलाइन के 320 बेड़े पर लागू है और 10 फरवरी, 2026 तक वैध है।

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए बड़ी राहत : किरेन रिजिजू ने दी तीन महीने की छूट

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार पंजीकरण की समय सीमा के बाद अगले तीन महीनों तक वक्फ कानून के तहत उम्मीद पोर्टल पर संपत्ति पंजीकृत करने वाले मुतवल्लियों पर जुर्माना नहीं लगाएगी या सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा कि कई सांसदों और सामाजिक नेताओं ने समय सीमा, जो 5 दिसंबर है, बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की समय सीमा के बाद इसे देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने मुतवल्लियों से आग्रह किया कि वे न्यायाधिकरण से संपर्क करें, क्योंकि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण को विस्तार देने का अधिकार है। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून बनाने के बाद, हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था और संबंधित पक्षों को पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। आज आखिरी दिन है, और लाखों संपत्तियां अभी भी पंजीकृत नहीं हुई हैं। कई सांसद और सामाजिक नेता मेरे पास समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने आए थे। अब तक, डेढ़ लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी मुतवल्लियों को आश्वस्त करता हूं कि अगले तीन महीनों तक, हम उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि आप पंजीकरण करने में असमर्थ हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप न्यायाधिकरण में जाएँ। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया था कि छह महीने की समय सीमा के बाद तारीख नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन न्यायाधिकरण के पास इसे छह महीने तक आगे बढ़ाने का अधिकार है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि केंद्र अधिकतम राहत तो देगा, लेकिन वह कानून से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को अधिकतम राहत देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें कानून से बंधी होती हैं। चूंकि संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित कर दिया है, इसलिए हम कानून में बदलाव नहीं कर सकते। इससे पहले सोमवार को, शीर्ष अदालत ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुझाव दिया कि आवेदक 2025 अधिनियम के अनुसार वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करके उक्त राहत प्राप्त करें।

हरियाणा खेल मॉडल वैश्विक नेतृत्व का बनेगा आधार - मुख्यमंत्री सैनी

चंडीगढ़।

हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई में आयोजित आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल आज केवल खिलाड़ियों तक सीमित विषय नहीं रह गया, बल्कि यह एक विशाल रोजगार, नवाचार और विज्ञान-आधारित क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने देशभर से आए शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह कॉन्फ्रेंस आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के खेल क्षेत्र का एक मजबूत रोडमैप तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य में खेल क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर राज्य की पहचान को नई ऊंचाई दी है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल प्रबंधन का भारतीयकरण केवल भारतीय प्रतीक या नाम अपनाना नहीं है, बल्कि अपने पारंपरिक खेल मूल्यों और आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन को एकीकृत करना है। उन्होंने बताया कि इस भारतीयकरण का आधार चार

खेलों में भारतीयकरण का आधार चार 'एम' — आधुनिकता, मानसिकता, प्रबंधन और नैतिक बेहद कारगर साबित होंगे

आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने की शिरकत

M—Modernity, Mindset, Management और Moral Values (आधुनिकता, मानसिकता, प्रबंधन और नैतिक मूल्य) हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय डेटा ड्रिवन, टेक-इनेबल्ड और साइंस सपोर्टेड स्पोर्ट्स का होगा, इसलिए भारतीय परिस्थितियों पर आधारित एक सशक्त प्रबंधन मॉडल विकसित करना अत्यावश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खेल क्षेत्र में 989 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जबकि इस वित्त वर्ष के बजट में 589 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

आज राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 382 इंडोर जिम, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल विकसित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटरों और आधुनिक स्टेडियमों का जाल गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 1,489 खेल नर्सरियां संचालित हो रही हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में हाई परफॉर्मेंस सेंटर और पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक भारतीय खेल तकनीकों को आधुनिक खेल बाजार से जोड़कर भारत एक नया "इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड" तैयार कर सकता है, जो देश के खेल मॉडल को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि खिलाड़ियों की प्रतिभा, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और आधुनिक प्रबंधन के समन्वय से भारत 2026 और 2028 के ओलंपिक में पदक तालिका में उल्लेखनीय सुधार करेगा।

उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस भारत के खेल भविष्य को नई दिशा देने वाली है। यहां रखे गए विचार आने वाले वर्षों में भारत के खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ेंगे। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को खेलों के माध्यम से मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर ने आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन खेलों में नवाचार को बढ़ावा देगा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलपति व पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस दो दिवसीय सेमिनार का उद्देश्य खेलों में भारतीय संस्कृति के समावेश को शामिल करना है। उन्होंने वर्ष 2022 में स्थापित खेल विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, राई से विधायक कृष्णा गहलावत, सोनीपत से विधायक निखिल मदान, विधायक पवन खरखोदा, मेयर राजीव जैन, अंतरराष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल- मोदी

■ पुतिन का भारत के राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत, दी गयी 21 तोपों की सलामी

■ राष्ट्रपति भवन में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

■ भारत ने रूस के लोगों के लिए मुफ्त वीजा का किया एलान, पुतिन बोले- भारत को बेरोकटोक तेल देते रहेंगे

नई दिल्ली।

पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया है। उन्होंने कहा,पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही है। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत-रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जबकि इसकी उम्मीद की जा रही थी। इसके बावजूद कई अहम घोषणाएं हुईं, जिनका मकसद भारत-रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत-रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले (पोलर) समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) पर समझौते और एमओयू साइन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और भविष्य की आर्थिक रूपरेखा पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। राष्ट्रपति पुतिन भारत आगमन पर मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और सार्थक वार्ता के लिए भारत नेतृत्व का आभार व्यक्त करते दिखाई दिए।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा- मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता को रूसी प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी भरे और सत्कारपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजभोज पर मेरी बातचीत हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए बहुत उपयोगी रही। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच वर्षों से स्थापित मजबूत संवाद प्रणाली लगातार सुदृढ़ हो रही है- प्रधानमंत्री मोदी और मैंने एक घनिष्ठ कार्यकारी संवाद स्थापित किया है।

हम एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे, और हम व्यक्तिगत रूप से रूस-भारत संवाद की देखरेख कर रहे हैं।

राष्ट्रपति पुतिन ने भारत-रूस व्यापारिक संबंधों में सकारात्मक प्रगति का उल्लेख किया कि पिछले वर्ष हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। हम वर्तमान में अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष का व्यापार समझौता उसी प्रभावशाली स्तर पर बना रहेगा। उन्हीं के अनुसार, दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ अब स्थिर और संरचित ढांचे में आगे बढ़ रही हैं।

पुतिन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों और चुनौतियों की एक महत्त्वपूर्ण सूची साझा की है जिन पर दोनों सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से इसमें मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश आपसी व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं- हमारे देश धीरे-धीरे राष्ट्रीय मुद्राओं में आपसी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, जो पहले से ही 96फीसदी वाणिज्यिक लेन-देन के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा साझेदारी को लेकर भी पुतिन ने आश्वस्त किया कि रूस भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार और भी विस्तृत करने पर काम होगा। संयुक्त प्रेस वार्ता ने यह स्पष्ट किया कि भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होने जा रही है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देने का वादा दोनों नेताओं ने किया।